संपादकीय जागरण

गुरुवार, 12 जुलाई, 2018 : आषाढ़ कृष्ण 14 वि. 2075

ईर्ष्या का जन्म स्वयं अपनी कमजोरियों से होता है

ताजमहल की अनदेखी

दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने वाले ताजमहल की देखभाल में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी स्वाभाविक ही है। ताजमहल विदेशी मुद्रा का एक बड़ा जरिया होने के साथ ही विश्व में भारत की पहचान का पर्याय भी है। ऐसी भव्य इमारत के संरक्षण के लिए तो ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि किसी को शिकायत का मौका ही न मिले। दुर्भाग्य से स्थिति इसके उलट दिख रही है और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई। समझना कठिन है कि ताजमहल सरीखी विशिष्ट इमारत की उचित देखभाल में आनाकानी का परिचय क्यों दिया जा रहा है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की बार-बार की टोका-टोकी के बावजूद स्थितियां बेहतर क्यों नहीं हो रही हैं? इसका कोई मतलब नहीं कि ताजमहल प्रदूषण से जूझने के साथ ही कई तरह की अव्यवस्थाओं से भी दो-चार होता हुआ दिखे। सुप्रीम कोर्ट न जाने कब से यह कह रहा है कि ताजमहल की सज-धज बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही अधिक नजर आ रहा है। यह विचित्र है कि ताजमहल के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। यह तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक उलट काम है जिसके तहत बरसों पहले उसने ताजमहल के आसपास की औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र स्थानांतरित किया था।

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भी कठघरे में खड़ा किया। इस विभाग के लिए ताजमहल एक नगीने की तरह है। यह सरकारी विभाग न तो दुनिया भर के पर्यटकों को आगरा खींच लाने वाले ताजमहल का सही तरह से संरक्षण कर पा रहा है और न ही राष्ट्रीय महत्व की अन्य इमारतों का। यह एक तथ्य है कि ताजमहल के मुकाबले अन्य पर्यटन स्थलों की स्थिति कहीं अधिक खराब है। कई प्राचीन स्मारक तो अनदेखी और अव्यवस्था के चलते खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। ऐतिहासिक महत्व की कुछ पुरानी इमारतें अतिक्रमण की भेंट चढ़ गईं, लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास इसका जवाब नहीं कि ऐसा क्यों हुआ? भारत उन चंद देशों में है जिसके पास बेजोड़ स्थापत्य कला का परिचय देने वाले अनगिनत इमारतें हैं, लेकिन उनकी उचित देखभाल नहीं हो पा रही है। इसके चलते ये इमारतें पर्यटकों को आकर्षित करने में उतनी सक्षम नहीं जितना कि उन्हें होना चाहिए। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार यह समझे कि स्मारकों के संरक्षण में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नाकामी बहुत महंगी साबित हो रही है। देश केवल अनमोल विरासत को ही नहीं खो रहा है, बल्कि विदेशी मुद्रा से भी वंचित हो रहा है। इसमें दोराय नहीं कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कठोर टिप्पणियों से बात बनेगी कि ताजमहल की देखभाल नहीं कर सकते तो फिर उसे ढहा दो। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन कारणों की तह तक जाए जिनके चलते ताजमहल और उसके साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण इमारतों की उचित देख-रेख नहीं हो पा रही है।

पुलिस पर हमला

सोमवार और मंगलवार को लगभग एक जैसी घटनाएं दो शहरों में हुईं। लखनऊ में एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल भरे बाजार छीन ली गई जबकि उधर औरैया में एक दारोगा ने नशा कर रहे लोगों को टोका तो वे हमलावर हो गए। उसे बचाने आये दूसरे दारोगा को भी उक्त युवकों ने दौड़ा लिया। अफसोस यह कि पुलिस ही पुलिस की मदद को नहीं पहुंची। दारोगा फोन मिलाते रहे, लेकिन न कोतवाल का नंबर लगा और न यूपी 100 का। जब तक दारोगा जी कोतवाली पहुंचते और वहां से कुछ सिपाहियों को लेकर मौके पर वापस जाते तब तक बदमाश भाग चुके थे। लखनऊ वाली घटना में सर्विस पिस्टल तो बरामद हो गई और बदमाश भी पकड़ लिया गया लेकिन तब तक दारोगा को निलंबित किया जा चुका था। पुलिस पर हमले की ये दो घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं लेकिन, इनकी पुनरावृत्ति न हो सके, यह सरकार को देखना होगा। वर्दी पर हमला बहुत दुस्साहस का काम है।

> किसी महिला की चेन का लुटना, किसी बेटी पर बुरी नजर पड़ना, दफ्तर जा रहे कर्मचारी की बाइक का छिन जाना उन्हें डराता है

किसी जेल में कोई माफिया मारा जाता है तो आम लोग प्रभावित नहीं होते। वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह राजनीति के समर्थन से लड़ी जा रही बड़े गिरोहों की लड़ाई है। आम लोग प्रभावित होते हैं छोटे कहे जाने वाले अपराधों से। किसी महिला की चेन का लुटना, किसी बेटी पर बुरी नजर पड़ना, दफ्तर जा रहे कर्मचारी की बाइक छिन जाना उन्हें डराता है। पड़ोसी के घर में चोरी हो जाना उन्हें डराता है। उत्तर प्रदेश में वर्षों से मित्र पुलिस की बातें हो रही हैं। जाने कितने ही अधिकारी इसके नाम पर विदेश भ्रमण कर चुके लेकिन आज तक पुलिस की छवि नहीं बदली। योगी सरकार को पुलिस की छवि सुधार की गंभीर पहल करनी होगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सबसे बड़े मोबाइल संयंत्र के लिए सैमसंग का निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते भरोसे को प्रदर्शित करता है?

आज का सवाल

क्या वनडे क्रिकेट में विराट कोहली को चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करनी चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

गठबंधन की खुलती गांठें

प्रदीप सिंह

गठबंधन की उठा-पटक केवल भाजपा और कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। इस वक्त देश की पूरी राजनीति में अविश्वास का दौर चल रहा है

रहीम का एक दोहा है- 'रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ि जाय।' निजी संबंधों की तरह ही राजनीतिक गठबंधनों के साथ भी ऐसा ही होता है। एक बार गांठ पड़ जाए तो उसका पहला शिकार आपस का भरोसा होता है। दोनों एक-दूसरे के प्रति शंकालु बने रहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड यानी जद-यू और भाजपा के साथ ऐसा ही हो रहा है। किसी भी राजनीतिक गठबंधन की दो बुनियादी शर्तें होती हैं। एक, इसमें दोनों का फायदा हो। दूसरा, एक दूसरे पर भरोसा हो। गठबंधन की इस गांठ का मामला केवल इन दो राजनीतिक दलों तक ही सीमित नहीं है। देश की पूरी राजनीति में ही अविश्वास का दौर चल रहा है। जद-यू और भाजपा का गठबंधन चलेगा या लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा, इस बारे में कोई भी पूरे भरोसे के साथ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं के बयानों को सुनें तो समझना मुश्किल है कि यह सब गठबंधन को चलाने के लिए बोला जा रहा है या तोड़ने के लिए? वैसे तो इसकी चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन जबसे कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पटना में पत्रकारों से जो कहा उससे लग रहा है कि कुछ तो है। गोहिल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार की तरफ से कोई महागठबंधन में शामिल होने का संदेश लेकर आया था। नीतीश कुमार के खेमे में कुछ लोग हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर रहने के बाद फिर लौटे हैं। वे चाहते हैं कि यह गठबंधन टूटे। ऐसे लोग नीतीश कुमार को समझा रहे हैं कि भाजपा बिहार में नंबर एक की पार्टी बनने के लिए आपकी हैसियत घटाएगी। महाराष्ट्र में भी भाजपा और शिवसेना का गठबंधन अधर में है। दोनों जगह समस्या यह है कि जहां छोटा भाई बड़ा भाई बनने को तैयार है वहीं छोटा ऐसा होने से रोकने की कोशिश कर रहा है।

शिवसेना लोकसभा में तो भाजपा से कम सीटों पर लड़ने को तैयार है, लेकिन विधानसभा में वह न केवल भाजपा से ज्यादा सीटें, बल्कि उसके विधायक कम आने की दशा में भी मुख्यमंत्री का पद चाहती है। नीतीश कुमार उससे थोड़ा ज्यादा चाहते हैं। उन्हें लोकसभा में भी भाजपा से ज्यादा सीट चाहिए, चाहे वह एक ही सीट क्यों न हो। गठबंधन में आखिरकार बातचीत से मामले सुलट भी जाते हैं। बशर्ते दोनों पक्षों को गठबंधन फायदे का सौदा लग रहा हो। बिहार में भाजपा को तय करना है कि नीतीश कुमार उसके लिए असेट हैं या लायबिलिटी हो गए हैं। नीतीश कुमार अब 2010 वाले सुशासन बाबू नहीं रह गए हैं। लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर उन्होंने काफी राजनीतिक पूंजी गंवा दी है। इसी तरह शराबबंदी से शुरुआती फायदे के बाद अब माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। शराबबंदी को लेकर बना कानून और बिहार पुलिस के भ्रष्टाचार ने इस अच्छी नीयत वाले काम को राजनीतिक रूप से घाटे का सौदा बना दिया है। नीतीश कुमार को पता है उनके सामने विकल्प बहुत ज्यादा नहीं हैं। 2014 में अकेले लड़कर देख चुके हैं। उस समय जो 17 फीसदी वोट मिले थे वे इस बार अकेले लड़ने पर नहीं मिलने वाले और उधर महागठबंधन के दरवाजे पर भतीजा लाठी लेकर खड़ा है कि चचा को घुसने नहीं देंगे।

अवधेश राजपूत

विपक्षी खेमे में अविश्वास कुछ ज्यादा ही है। मोदी को हराने के लिए आओ सब एक हो जाएं का नारा तो लग गया है, लेकिन जमीन पर वैसा होता हुआ फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। राजनीति की दृष्टि से देश के सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश को ही लें। चार उपचुनाव जीतकर विपक्ष बम-बम था, लेकिन समय के साथ उत्साह घटता दिख रहा है। कैराना लोकसभा उपचुनाव के बाद मायावती ने गोरखपुर और फूलपुर की तरह से न तो कोई बयान दिया और न ही अखिलेश यादव से मिलीं। कहते हैं कि अखिलेश यादव ने मिलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। मायावती ने कैराना की नई सांसद तबस्सुम हसन को भी मिलने का समय नहीं दिया। दरअसल मायावती के लोगों को इस बात का भरोसा नहीं है कि सपा अपने वोट बसपा उम्मीदवारों को दिलवा पाएगी। इसके अलावा सपा नहीं चाहती कि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बने। अब यह पता नहीं कि यह 2017 के विधानसभा चुनाव के कड़वे अनुभव का नतीजा है या इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोई भूमिका है?

राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के सूत्रधार माने जा रहे शरद पवार कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले किसी गठबंधन की बात अव्यावहारिक है। ममता बनर्जी भी विपक्षी एकता के लिए सक्रिय हैं, लेकिन उनका फार्मूला क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बनाने का है। जाहिर है कि उनकी रणनीति कांग्रेस को किसी भी गठबंधन से बाहर रखने की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुखिया और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ममता बनर्जी के साथ हैं। अखिलेश यादव भी उनसे सहमत हैं। मायावती से गठबंधन के लिए कांग्रेस बहुत आतुर थी। उसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में तत्काल फायदा मिलता दिख रहा था, लेकिन मायावती इस बारे में अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं। यहां भी उनकी चिंता वही है जो अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में है। सिर्फ दो राज्य हैं जहां कांग्रेस का गठबंधन तय लग रहा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो घोषणा कर चुकी है कि कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में भी कांग्रेस को जनता दल-सेक्युलर के रूप में नया साथी मिला है। जद-एस के कुमारस्वामी और उनके पिता देवेगौड़ा मिलकर चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पिता-पुत्र को साधना आसान नहीं होगा।

गठबंधन को लेकर समस्याएं भाजपा और कांग्रेस दोनों के समक्ष हैं। इसके बावजूद कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब दिख रही है और इसका कारण है दोनों दलों के नेता के नेतृत्व की वोट दिलाने की क्षमता। गठबंधन करने वाली पार्टी दो बातें देखती है। एक, क्या गठबंधन का हमारा साथी हमें अपने वोट दिला पाएगा? दूसरा, क्या सत्ता में भागीदारी मिलने की संभावना है? दूसरी बात तो बाद की बात है। पहले सवाल वोट का है। चुनाव दर चुनाव साबित हो चुका है कि राहुल गांधी के नाम पर लोग वोट देने को तैयार नहीं हैं। गुजरात में वह 22 साल की एंटी इनकंबंसी के बावजूद वह अपनी पार्टी को जिता नहीं सके और कर्नाटक में अपनी सरकार की उपलब्धि को भुना नहीं सके। इसके बरक्स चार साल पहले राष्ट्रीय राजनीत में आए नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि भाजपा में आज तक उनसे बड़ा वोट दिलाने वाला नेता नहीं हुआ। इसमें अमित शाह के संगठन कौशल की अहम भूमिका है। केंद्र सरकार की चार साल की एंटी इनकंबंसी के बावजूद आम लोगों में मोदी की विश्वसनीयता के मुकाबले राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते। इसके लिए किसी भाजपा नेता से पूछने की जरूरत नहीं है। यह सवाल किसी भी विपक्षी दल के नेता से पूछ लीजिए, जवाब एक ही मिलेगा।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

मुसीबत बनता राहत देने वाला कानून

क्षमा शर्मा

महिलाओं की सहूलियत के लिए मातृत्व अवकाश में वृद्धि का फैसला उनकी नौकरियों की बलि ले रहा है

अरसा पहले दिल्ली के कुछ बड़े निजी संस्थानों के बारे में यह मशहूर था कि वहां लड़कियों को नौकरी नहीं दी जाती। इसके पीछे तर्क यह था कि लड़कियां आएंगी, शादी करेंगी, मां बनेंगी तो काम पर कब ध्यान देंगी, लेकिन वक्त बदला और बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़-लिखकर नौकरी करने लगीं। घर और कॅरियर, दोनों उनके जीवन का हिस्सा बना। उनकी जरूरतों को देखते हुए सरकारी क्षेत्र ने तो बदलाव किए ही, निजी क्षेत्र ने भी अपनी महिला कर्मचारियों के हित में बहुत से कदम उठाए। लगभग दो साल पहले कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने यहां उन महिलाओं को नौकरी देने की पहल की जो बच्चे के जन्म के कारण नौकरी छोड़ देती हैं। कंपनियों का कहना था कि बच्चे का जन्म खुशी की बात है, कोई अपराध नहीं। निःसंदेह यह कोई अच्छी बात नहीं कि महिलाएं इसलिए नौकरी न कर सकें कि बच्चे के कारण काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगी। निजी क्षेत्र के कुछ संस्थानों ने अपने यहां काम करने वाली महिलाओं को ओवम बैंक (अंडाणु बैंक) में अपने अंडाणु सुरक्षित रखने की सुविधा भी दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दिनों लड़कियां अपनी पढ़ाई-लिखाई और कॅरियर में इतनी व्यस्त रहती हैं कि जब तक मां बनने का खयाल आता है, मां बनने की उम्र निकल जाती है। अगर उनके अंडाणु सुरक्षित हैं तो विज्ञान की उच्चतर तकनीक जैसे आइवीएफ या सरोगेसी के जरिये वे मां बनने का सुख प्राप्त कर सकती हैं। हाल में जब महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की पहल पर औरतों के मातृत्व अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर, 26 हफ्ते कर दया गया तो इसे बहुत प्रगतिशील कदम माना गया, लेकिन हाल में टीमलीज नामक कंपनी ने अपने अध्ययन में यह पाया कि छह महीने के मातृत्व अवकाश के कारण हो सकता है कि करीब सवा करोड़ औरतों की नौकरी चली जाए। इस अध्ययन के दौरान बहुत से नियोक्तओं से बात की गई थी। इनमें उड्डयन, बीपीओ, सूचना एवं संचार तकनीक, ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, पर्यटन आदि बड़े उद्योगों के लोग शामिल थे।

टीमलीज के अधिकारियों का मानना था कि तमाम नियोक्ता लंबे मातृत्व अवकाश को एक घाटे का सौदा मानते हैं। हालांकि बहुत सी प्रगतिशील कंपनियां पहले से ऐसा कर रही हैं। बड़ी कंपनियों और मध्यम दर्जे की कंपनियों के अधिकारियों ने महिलाओं को दी जाने वाली इस सुविधा का आम तौर पर स्वागत किया था, लेकिन जिनका सालाना राजस्व दस-बीस करोड़ है वे इसे कंपनी के नुकसान के रूप में देख रहे हैं। ध्यान रहे अपने देश में बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी ही कंपनियों में काम करती हैं। जो लोग बच्चे के जन्म पर मां को दिए जाने वाले छह महीने के अवकाश को घाटे का सौदा मान रहे हैं उनका कहना है कि छह माह महिला कोई काम नहीं करेगी और फिर भी उसे पूरा वेतन देना होगा। उनका यह भी तर्क है कि जहां ज्यादा महिलाएं हैं वहां कंपनियां उनके काम की भरपाई कैसे करेंगी? कंपनियों को उनकी जगह अस्थाई कर्मचारी रखने पड़ेंगे। इस तरह मातृत्व अवकाश पर गईं महिलाओं को तो वेतन देना ही होगा, उनकी जगह काम पर रखे गए अस्थाई कर्मचारियों को भी पैसे देने होंगे। जाहिर है निजी क्षेत्र की कंपनियों पर दोहरी मार पड़ेगी। छोटी कंपनियां इस तरह के खर्चे उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनकी यह दलील होती है कि इतनी कमाई ही नहीं है।

कई कंपनियों के लोग कह रहे हैं कि सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन जब तक सरकारें इस बारे में सोचेंगी तब तक कंपनियां हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वालीं। सच तो यह है कि उन्होंने यह एक आसान सा रास्ता निकाला है कि महिलाओं को नौकरी ही न दी जाए। न महिलाएं होंगी, न उन्हें छह महीने की छुट्टी देनी होगी। अगर छोटी कंपनियों में महिलाओं को नौकरी देने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार उनकी कुछ आर्थिक मदद करती भी है तो आखिर वे बड़ी कंपनियां जो सवैतनिक छह महीने की छुट्टी दे रही हैं, नुकसान में क्यों रहें? जाहिर है बड़ी कंपनियां भी इसी तरह की मांग कर सकती हैं। वैसे भी व्यापार का पहला नियम मुनाफा कमाना होता है, समाज सुधार या लैंगिक समानता का विचार नहीं। ऐसा लगता है सरकार ने कानून में परिवर्तन तो औरतों की मदद के लिए किया था, लेकिन वह उनकी नौकरियों की बलि ही लेने लगा। कहीं वे दिन वापस तो नहीं लौट रहे हैं जब तमाम संस्थान महिलाओं को नौकरियां देने से कतराते थे? जो भी हो, यह सही नहीं कि महिलाओं को एक तरह से यह बताने की कोशिश हो रही है कि मां बनना तुम्हारा निजी मामला है। इसके लिए जहां नौकरी करती हो वहां से कोई उम्मीद न रखना। निःसंदेह यह ठीक नहीं होगा कि बच्चे के जन्म के कारण महिलाओं को दंडित होना पड़े। आखिर इससे बड़ा भेदभाव क्या हो सकता है?

टीमलीज रिपोर्ट में साढ़े तीन सौ स्टार्टअप और मंझोली एवं छोटी कंपनियों का सर्वेक्षण किया गया था। इनमें से तमाम कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अपने यहां महिलाओं को काम पर रखना बंद कर दिया है। इससे यही साबित होता है कि मात्र कानून बनाने से समाज कभी नहीं बदलता। कानून के साथ मानसिकता को भी बदलना होता है। बराबरी का नारा सिर्फ दिखावटी हो और लोगों को उसके मुकाबले अपने मुनाफे का गुणा-भाग ज्यादा लुभाता हो तो बदलाव मुश्किल से ही आता है। उसे रोकने का कोई न कोई बहाना और कारण ढूंढ़ ही लिया जाता है।

विश्व बैंक की मानें तो लगभग दो करोड़ औरतों की नौकरियां 2004 से 2012 के बीच जा चुकी हैं। लंदन, न्यूयार्क और पेरिस की कुल आबादी लगभग दो करोड़ ही है। एक दूसरे अध्ययन में भी यह पाया जा चुका है कि एक दशक पहले कुल कमागारों में महिलाओं की संख्या 36 प्रतिशत थी जो अब घटकर 24 प्रतिशत रह गई है। आखिर यह कहां का न्याय है कि अपने देश में एक ओर मां दुनिया में सबसे आदरणीय मानी जाए और दूसरी ओर मां बनने के कारण उसे छुट्टी जैसी सुविधा देना तो दूर, उसकी नौकरी ही ले ली जाए? आखिर दुनिया में एक शिशु का आना इतना आफत भरा क्यों है?

(लेखिका साहित्यकार एंव स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वयं को बदलें

क्या यह जानते हैं कि आप कौन हैं और कहां पर हैं? यह सवाल जिंदगीभर अधूरा रह जाता है, क्योंकि आप लोग इसे समझना नहीं चाहते और यूं ही जीते चले जाते हैं। इसलिए आपको बदलना होगा। धर्म की परिभाषा बदलनी होगी। कर्म की परिभाषा बदलनी होगी। धर्म को मनुष्यों द्वारा संचालित करना होगा। आपका धर्म ईश्वर की कृपा और देवी-देवताओं के नाम पर संचालित है, जो अच्छी बात है, लेकिन विडंबना यह है कि आपका धर्म गुरुओं के नाम से संचालित हो रहा है। यह आम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें मनुष्य के कर्म को दोषी ठहराया गया है। इसे पाप-पुण्य से जोड़ दिया गया है। आप लोग पूजा, प्रार्थना आदि में किसी और के हिस्से का अर्पित कर रहे हैं, स्वयं को समझे बिना कि आप कौन हैं? इसलिए आपको सफलता नहीं मिलती।

मैं चाहता हूं कि धर्म के गुण में परिवर्तन हो, इसे सत्य से जोड़ा जाए। इसके लिए हममें से हरेक को अपनी चेतना के साथ जीना होगा। यह तभी संभव है, जब हर आदमी अपनी खोज में निकल जाए। आप अपने बारे में सोचें और अपने आसपास के लोगों को देखें। यह आपका एक छोटा सा संसार है, जो बड़ा बन जाता है। आप सब धार्मिक हैं। हो सकता है कि कुछ लोग धार्मिक नहीं भी हों, लेकिन आप सबकी अपनी-अपनी दिनचर्याएं हैं। जो धार्मिक हैं, वे विभिन्न विचारधाराओं में बंटे हुए हैं। उनका मत भिन्न-भिन्न है। उनमें मतांतर है। अलग पूजा पद्धतियां हैं।

आम तौर पर इनमें एक-दूसरे के प्रति सहज-स्वाभाविक प्रेम नहीं है। कहने को तो ये धर्म पालक हैं, पर इनकी शिक्षा में प्रेम का अभाव रहा है। फिर ऐसे लोग दुखी क्यों न हों। इनमें से ज्यादातर जीवन को नहीं समझते, धर्म को नहीं जानते, जो सिखाया गया है, उसी में मोक्ष की कामना लिए जीवन मार्ग पर समय काट रहे हैं। इन्हें लगता है कि वह जो कर रहे हैं वही उनका सत्य है। जो मान रहे हैं, वही उनका भगवान है। उनसे अलग जो दुनिया है, वह पापियों की दुनिया है। इसलिए वे ही अच्छे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, जो अपने अस्तित्व और ईश्वर साक्षात्कार की तलाश में ईमानदारी से लगे हुए हैं और धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। उसे वास्तविक रूप से समझने के लिए हमें समग्रता के साथ विचार करना होगा।

महायोगी पायलट बाबा

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सेना पर ध्यान दे सरकार

सामरिक मोर्चे पर सुस्त रफ्तार शीर्षक से लिखे अपने लिख में सी उदयभास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए वादों के अनुरूप सुधार न कर पाने का जिक्र किया है। यह संदेह से परे है कि देश में जब मोदी सरकार आई तब अर्थव्यवस्था को नई जान मिली। दुनिया में देश को एक अलग ही पहचान मिली। देशवासियों को स्वच्छता का एक नया विचार मिला। देश के सैनिकों को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का अधिकार मिला। पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का लाभ भी मिला। मोदी सरकार ने इन चार सालों में रक्षा क्षेत्र से जुड़े अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। लेकिन सेना के आधुनिकीकरण और सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद भी वेतन बढ़ोतरी तथा अन्य लाभों में सुधार की मांग को अभी तक स्पष्ट रूप से अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। सेनाएं पेट के बल चलती हैं। इसलिए सेना की मजबूती और विकास के लिए सर्वप्रथम उनकी मांगों पर फौरी तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसे नजरअंदाज करने का मतलब 13 लाख संख्या वाली विस्तृत सेना के मनोबल को कमजोर करना है। आज के समय में युद्ध सेना के आकार से नहीं अपितु तकनीकी के प्रकार से लड़ा जाता है। लेकिन जिसकी कमी देश में आज भी जस की तस है। आज भी हम युद्ध के साजोसामान के लिए महाशक्तियों का मुंह ही ताकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर हम कब तक युद्ध लड़ सकते हैं। जब तक हम स्वयं का कंधा मजबूत नहीं करेंगे तब तक सेना के आधुनिकरण की परिकल्पना को कभी साकार नहीं कर सकते। बल से बड़ी बुद्धि होती है। इस दायित्व का निर्वहन सेना के विशेषज्ञ अधिकारी ही करते हैं। सेना में इनकी विशेष महत्ता होने के बावजूद भी अनेकों पद खाली हैं। सरकार द्वारा रक्षा अध्ययन से जुड़े विषयों की पढ़ाई के विस्तार को भी महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि देश में इसे एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। नीति बंदूक की गोली से दो कदम आगे चलती है, लेकिन स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने और सेना के आधुनिकरण के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां बंदूक की गोली से दो कदम पीछे ही चल रही हैं।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

बच्चों के साथ शर्मनाक व्यवहार

स्कूल में बच्चों के साथ आए दिन कोई न कोई घटना सामने आ रही हैं। कुछ महीने पहले गुड़गांव में सात साल के प्रद्युम्न की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, वहीं अब दिल्ली में स्कूल की फीस जमा नहीं करने पर प्राथमिक विद्यालय की 16 बच्चियों को बेसमेंट में बंधक बना दिया गया। ऐसे कई मामले रोज देखने को मिल रहे हैं जिनमें छात्रों के साथ शारीरिक शोषण जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बहुत ही शर्मनाक है।

archanagitakeshri@gmail.com

जनसंख्या की समस्या

बढ़ती जनसंख्या की समस्या केवल भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों की भी है। बढ़ती जनसंख्या इस समय भयावह रूप धारण कर रही है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण रहने के स्थान के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, इस प्रकार अन्न उपजाने वाली भूमि भी कम होती जा रही है। इतनी अधिक जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेतों में अनियंत्रित रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर अन्न उपजाया जा रहा है। साथ ही लोगों के रोजगार के लिए जंगलों को साफ कर केवल कल-कारखाने लगाए जा रहे हैं। इनसे होने वाले प्रदूषण हमारे तथा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक हैं। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

ankitkr398@gmail.com

शादियों में फिजूलखर्ची

आजकल शादियों में लोग इतना फिजूल खर्च करते हैं, शायद उन्होंने इतना खर्च अपने बच्चों की शिक्षा पर भी नही किया होगा। शादियों में बड़े-बड़े फार्म हाउस बुक होते हैं, शादी के कार्ड्स से लेकर खाने पर खूब पैसा बहाया जाता है। पहले तो दहेज केवल जेवरों तक सीमित था, लेकिन अब लोग महंगी गाड़ियां इत्यादि भी दहेज में देते हैं। लड़के वाले इस पर ये सफाई देते हैं कि उन्होंने तो मांगा नहीं और चुपचाप उसे रख लेते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि अगर लड़की दहेज ना लाए तो उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है। बेहतर यही होगा कि दोनों पक्ष ये समझें कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। विशेषकर लड़की वालों को ये समझना चाहिए कि वे अपनी लड़की को शिक्षित और आत्मनिर्भर बना कर विदा करें और ऐसे लोगों से कतई रिश्ता न करें जो दहेज के भूखे हों। हालांकि सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए कई कानूनों को लागू किया है, लेकिन इनमें और सख्ती बरतने की जरूरत है। दहेज देने और लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि शादी जैसे पवित्र अवसर पर फिजूल खर्च के बजाय इसे कम से कम लोगों की मौजूदगी में संपन्न करके समाज में एक उदाहरण पेश करें। इसके लिए सबसे पहले समाज के जिम्मेदार लोगों को आगे आना होगा। जब मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़े अधिकारी अपने बच्चों का विवाह सादे समारोह में करेंगे तो समाज को एक संदेश जाएगा। अन्य लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। टीवी सीरियल में भी शादी-विवाह के भव्य समारोह के बजाए सादे शादी-विवाह को दिखाया जाना चाहिए। इस तरह दहेज रूपी बुराई को रोका जा सकता है।

पिंकी, खेड़ा कलां, दिल्ली

ट्वीट-ट्वीट

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़कों पर गड्ढों की संख्या में भारी कमी आई है। उनका कहना सही है, क्योंकि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो सड़क पानी से ढक जाएगी और आप चाहकर भी सड़कों पर गड्ढे नहीं देख सकते।

कबीर बेदी@iKabirBedi

ट्विटर पर दाहिने कोने पर एक गोला है। लिखते जाइए। वह जगह भरने का संकेत देने लगता है। आखिर में पीला हो जाता है यानी खतरा, फिर लाल यानी अब जगह नहीं। यही हाल उस गोले (पृथ्वी) का भी है जिस पर हम रह रहे हैं। संसाधन खत्म हो रहे हैं। पीले/लाल सिग्नल को इग्नोर कर रहे हैं हम।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

तकनीक के दम पर हमने मौत पर कुछ हद काबू पा लिया है। समय आ गया है कि जन्म यानी आबादी को लेकर भी कुछ नियंत्रण करें। इस ग्रह को बचाना है तो बढ़ती आबादी जैसी बड़ी चुनौती से कारगर ढंग से निपटना होगा।

सद्गुरु-जग्गी वासुदेव@SadhguruJV

जो देश ताजमहल जैसी अनमोल धरोहर को सही तरह से सहेजकर नहीं रख सकता फिर उसे दुनिया भर से सैलानियों को लुभाने के लिए अतुल्य भारत जैसे प्रचार अभियान भी नहीं चलाने चाहिए।

राजदीप सरदेसाई@sardesairajdeep

जनपथ

मरने से तो बच गए बारह बच्चे-कोच,
किंतु गूढ़ इक बात मैं रहा बैठकर सोच।
रहा बैठकर सोच कौन सी थी वह माया,
जिसे दिखाने कोच गुफा में लेकर आया!
दे जोखिम में जान गया क्या उसमें करने,
बच्चों को भी साथ ले गया बुद्धू मरने।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 358